

GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]

दिल्ली, शनिवार, जून 16, 2018/च्येष्ठा 26, 1940

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 547]

No. 130]

DELHI, SATURDAY, JUNE 16, 2018/ JYAISTHA 26, 1940

[N.C.T.D. No. 547]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार और कर विभाग

[नीति (जीएसटी) शाखा]

अधिसूचना

दिल्ली, 15 जून, 2018

सं. 3 / 2018

फा. सं. 3 (163)/नीति/जीएसटी/2018/298–307.—दिल्ली माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 138 के उपनियम (14) के खंड (घ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं. सं. फा. 3(134)/नीति/जीएसटी/2018/1626.36 दिनांक 28/03/2018 के अधिग्रहण में, मैं, एच. राजेश प्रसाद, आयुक्त (राज्य कर), दिल्ली, मुख्य आयुक्त (केन्द्रीय कर) के परामर्श से, एतदद्वारा अधिसूचित करता हूँ कि दिल्ली राज्य के अधीन आने वाले क्षेत्र में अंतरा-राज्यीय (अंतर-राज्य परिचालन के भीतर समाप्त होने पर, लेकिन किसी भी अन्य राज्य से गुजरने के बिना) परिचालन हेतु ई-वे बिल को सृजित करने की अपेक्षा नहीं होगी, जहां माल का मूल्य 1,00,000/- से अधिक नहीं है।

इसके अलावा, सभी माल, चाहे किसी भी मूल्य के हो, जिसकी आपूर्ति कर योग्य व्यक्ति के पंजीकृत व्यावसायिक स्थान से एक अपंजीकृत अंत उपभोक्ता तक परिचालन में है और उसके साथ दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 31 के तहत जारी एक चालान हो, अंतरराज्यीय परिचालन के लिए ई-वे बिल को सृजित करने की भी अपेक्षा नहीं होगी।

हालांकि, कर चालान, आपूर्ति बिल, वाउचर, डिलीवरी चालान या प्रवेश के बिल जैसे दस्तावेज, अंतर राज्य ई-वे बिल से छूट के माल के संबंध में साथ रखने की आवश्यकता होगी।

2. यह अधिसूचना जून 16, 2018 से लागू होगी।

3. अधिसूचना सं. सं. फा. 03(134) / नीति / जीएसटी / 2018 / 1626.36 दिनांक 28/03/2018 एतद्वारा रद्द की जाती है।

एच. राजेश प्रसाद, आयुक्त (राज्य कर)

DEPARTMENT TRADE AND TAXES

[POLICY (GST) BRANCH]

NOTIFICATION

Delhi, the 15th June, 2108

No. 3/2018

F. No. 3(163)/ POLICY (GST/2018/298-307).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-rule (14) of rule 138 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 and in supersession of notification No. F. No. 3(134)/Policy-GST/2018/1626-36 dated 28/03/2018, I, H. Rajesh Prasad, Commissioner, State Tax, in consultation with the Chief Commissioner of Central Tax, do hereby notify that the no e-Way Bill in respect of movement of goods originating and terminating within the State of Delhi (intra-State movement but without passing through any other State) shall be required where the consignment value does not exceed Rs.1,00,000/- (rupees one lakh only).

Further all goods, irrespective of any value, the supply of which is from the registered business place of a taxable person to an unregistered end consumer and the movement is accompanied by an invoice issued under Sec 31 of the Delhi Goods & Services Tax Act shall also be exempted from the requirement of e-Way Bill for intra-State movement.

However, documents such as tax invoice, bill of supply, voucher, delivery challan or bill of entry, as the case may be, shall be required to be carried even in respect of consignments exempted from intra-State e-Way Bill.

2. This Notification shall come into force with effect from the 16th day of June, 2018.

3. Notification No. F. No. 3(134)/Policy-GST/2018/1626-36 dated 28/03/2018 is hereby rescinded.

H. RAJESH PRASAD, Commissioner (GST)